

संख्या-167/XXIV-4/2006

प्रेषक,

एसओके०माहेश्वरी,  
राचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
विद्यालयी शिक्षा,  
उत्तरांचल, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून:दिनांक 21 अगस्त, 2006

विषय— टी०एच०डी०सी० द्वारा संचालित उ०मा०वि० भानियावाला,  
देहरादून एवं उ०मा०वि० पथरी, हरिद्वार का प्रान्तीयकरण/  
अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- नियो०-1/2119/  
टी०एच०डी०सी० (प्रान्तीयकरण)/2005-06 दिनांक 21, अप्रैल, 2005 एवं  
नियो०-1/7198/टी० एच० डी० सी० (प्रान्तीयकरण/ अधि०)/2006-07  
दिनांक 25 मई, 2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री  
राज्यपाल महोदय टी०एच०डी०सी० द्वारा संचालित उ०मा०वि० भानियावाला,  
देहरादून एवं उ०मा०वि० पथरी, हरिद्वार का प्रान्तीयकरण/अधिग्रहण  
शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा वास्तविक रूप से अधिग्रहण की तिथि  
जो भी बाद में हो, से किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त विद्यालयों में कार्यरत स्टाफ का शिक्षा विभाग में  
आमेलन/समायोजन शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन रहेगा।

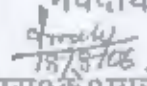
3— प्रान्तीयकरण की तिथि से उक्त विद्यालयों का सम्पूर्ण व्यय  
राजस्व आय-व्ययक से सीधे सरकारी खर्च के रूप में वहन किया जायेगा तथा  
अन्य राजकीय विद्यालयों की भाँति इन विद्यालयों को भी जिला शिक्षा  
अधिकारी के प्रशासनिक अधिकार में दिया जायेगा जो शिक्षा निदेशक  
उत्तरांचल द्वारा प्रसारित सामान्य नियमों के अनुसार इसका संचालन करेंगे।  
प्रश्नगत विद्यालयों की भूमि/भवन आदि सभी चल तथा अचल सम्पत्ति का  
शासन को स्थानान्तरण कर दिया जायेगा। विद्यालयों की आय में  
(प्रान्तीयकरण की तिथि से तथा विद्यालयों की अवशेष क्लेम की बकाया रकम,  
कोष बन्दे से प्राप्त रकम, दान से प्राप्त धनराशि तथा छात्रों से ली गई फीस  
की धनराशि सम्मिलित है) राजस्व प्राप्ति के अन्तर्गत प्राप्त आय सम्बन्धित  
शीर्षक में जमा कर दी जायेगी। प्रान्तीयकरण पर ये विद्यालय बिना दायित्व  
तथा अन्य भार के शासन को सौंप दिये जायेंगे। प्रान्तीयकरण से पहले की  
देनदारी यदि बाद में निकल आयी, तो उसका दायित्व शासन पर नहीं होगा।

4. उक्त विद्यालय में शिक्षकों आदि की नियुक्ति/समायोजन नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। इन पदधारकों की ज्येष्ठता का निर्धारण का पूर्ण अधिकार शासन तथा शिक्षा विभाग को होगा। इन पदधारकों को राजकीय सेवा में स्थायी रूप से विलीनीकरण करना तभी सम्भव होगा, जब ये सक्षम अधिकारी अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा अन्ततः योग्य घोषित कर दिये जायेंगे। ऐसे प्रश्नगत स्टाफ को वेतन सामान्य नियमों के अन्तर्गत निर्धारित होगा।

5. ऐसा पदधारक जो निर्धारित योग्यता न रखते हों अथवा जिन्हें सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न हो, का सरकारी सेवा में स्थायी रूप से विलीनीकरण सम्भव न होगा।

6- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखा शीर्षक -2202-सामान्य शिक्षा-02-माध्यमिक शिक्षा-आयोजनेत्तर-109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय-08-अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण के नामे डाला जायेगा।

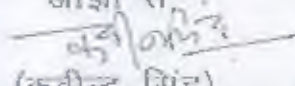
7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 404 / वित्त अनु0-3/2006 दिनांक 17-08-2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
  
 (एसओ के माहेश्वरी)  
 सचिव।

संख्या-167 (1)/XXIV-4/2006 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/मा० शिक्षा मंत्री जी।
3. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून/हरिद्वार।
6. जिला शिक्षा अधिकारी देहरादून/हरिद्वार।
7. निदेशक कार्गिक टी०एच०डी०सी०, ऋषिकेश, देहरादून
- 08 एन०आई०सी०, उत्तरांचल, देहरादून ✓
09. वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ।
10. मार्ट फाईल।

आज्ञा से  
  
 (कवीन्द्र सिंह)  
 अनु सचिव।